basis of the recommendations of the Agricultural Prices Commission, which takes into account all relevant factors.

(c) For 1975-76 season, the statutory minimum price of raw jute had been fixed at Rs. 135/- per quintal for Assam Bottom and comparable varieties at all upcountry markets, by Government of India, and not by Jute Corporation of India.

(d) Jute Corporation of India is engaged in purchase and sales including Imports and Exports of raw jute and not of jute products.

Loan Scheme for Rubber Grower

1855. SHRI PRABODH CHANDRA:
SHRI M. RAM GOPAL REDDY:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal with Government to modify replanting loan scheme for rubber growers in the country; and

(b) if so, the main features thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) There is no loan scheme for replanting rubber. But there is a Replanting Subsidy Scheme under which Subsidy is paid to the rubber growers by the Rubber Board. The scheme has already been modified with effect from 1st April, 1975.

(b) Government have enhanced the subsidy from the rate of Rs. 2471 per hectare in force till 31st March 1975 to the rate as indicated below with effect from 1st April 1975:—

(i) Holdings upto 2 hectares—Rs. 7500 per hectare.

(ii) Holdings above 2 hectares and upto 20 hectares—Rs. 5000 per hectare.

(iii) Estates above 20 hectares—Rs. 3000 per hectare.

The above mentioned enhanced rates of subsidy have also been extended in respect of the remaining instalments of subsidy payable to the rubber growers during 1975-76 onwards for the replantings undertaken by them in the years 1969 to 1974.

सम्पत्ति का स्वयं ब्यौरा देना

1856. श्री लाल जी भाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विभिन्न आयकर आयुक्तों को कितने व्यक्तियों ने अपनी सम्पत्ति का स्वेच्छा से ब्यौरा दिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : आय तथा धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 (आय तथा धन का स्वेच्छया प्रकटन अधिनियम, 1976) की धारा 15(1) के अन्तर्गत, शुद्ध धन अथवा उन परिसम्पत्तियों के मूल्य के संबंध में घोषणा की जा सकती थी, जिन को प्रकट नहीं किया गया था अथवा जिन का मूल्य कम बताया गया था । तत्काल उपलब्ध सूचना के आधार पर, आयकर आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र वार ऐसी घोषणाओं की संख्या का एक विवरण पत्र संलग्न है ।

धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 18 (2ए) तथा 18 बी के अन्तर्गत स्वेच्छा से किये गये प्रकटीकरण के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे देश भर के धन कर आयुक्तों से एकत्र करना पड़ेगा । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के संबंध में सूचना चाहते हों, तो उसे एकत्र कर के प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।